Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

सर छोटू राम का औद्योगिक विकास में योगदान: औपनिवेशिक पंजाब के आर्थिक पुनर्निर्माण का एक ऐतिहासिक अध्ययन

ललित कुमार [1*], राम सिंह गुरना [2]

[1] पी.एच.डी. शोधार्थी, इतिहास विभाग, देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोविन्दगढ़, पंजाब, भारत

[2] शोध निर्देशक एवं प्रोफेसर, इतिहास विभाग, देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोविन्दगढ़, पंजाब, भारत

Corresponding Author: * ललित कुमार

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20490955

सारांश

सर छोटू राम (1881–1945) औपनिवेशिक भारत के उन गिने-चुने राजनेताओं में से थे जिन्होंने न केवल कृषि सुधारों की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए, बल्कि पंजाब के औद्योगिक विकास को भी एक ठोस आधार प्रदान किया। यह शोध पत्र उनके उन प्रमुख योगदानों का विश्लेषण करता है जो उन्होंने पंजाब की मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और स्वदेशी उद्योगों को प्राथमिकता देने के संदर्भ में किए। उनके कार्यकाल में पंजाब में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1936 में 71 से बढ़कर 1938 में 98 हो गई, और वार्षिक निवेश 13 लाख रुपये से बढ़कर 24 लाख रुपये हो गया। यह शोध उनकी नीतियों, भाषणों और विधानसभा में की गई पहलों के माध्यम से उनकी समग्र दृष्टि को प्रस्तुत करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 04-04-2026
- **Accepted:** 31-05-2026
- **Published:** 01-06-2026
- **MRR:**4(5); 2026: 381-385
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

ललित कुमार, राम सिंह गुरना. सर छोटू राम का औद्योगिक विकास में योगदान: औपनिवेशिक पंजाब के आर्थिक पुनर्निर्माण का एक ऐतिहासिक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(5):381-385.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: सर छोटू राम, औद्योगीकरण, औपनिवेशिक पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी, स्वदेशी उद्योग, कृषि-औद्योगिक विकास, श्रमिक अधिकार, किसान राहत कोष।

© 2026 ललित कुमा, राम सिंह गुरना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के संधिकाल में औपनिवेशिक भारत एक गहरे आर्थिक संकट से गुज़र रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुँचाई थी। भारत का कच्चा माल सस्ते दामों पर ब्रिटेन निर्यात किया जाता था और वही माल निर्मित वस्तुओं के रूप में कई गुना महँगे दामों पर भारत में वापस बेचा जाता था। इस असमान व्यापारिक व्यवस्था का सबसे अधिक दुष्प्रभाव पंजाब जैसे कृषि-प्रधान प्रांतों पर पड़ा, जहाँ किसान और कारीगर आर्थिक शोषण के शिकार थे। इसी संकटकाल में सर छोटू राम एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे जिन्होंने पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आधार देने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया। वे सर फ़ज़ल-ए-हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रांत की सरकार चलाते रहे और इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास को अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं में केंद्रीय स्थान दिया। उनका स्पष्ट मत था कि कृषि अकेले प्रांत को पर्याप्त समृद्धि नहीं दे सकती इसलिए उद्योगों की स्थापना अनिवार्य है।

2. ऐतिहासिक संदर्भ: औपनिवेशिक आर्थिक शोषण

सर छोटू राम के औद्योगिक विचारों को समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें वे काम कर रहे थे। उपनिवेशकालीन आर्थिक संरचना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे शोषण का शिकार बनाया था। सर छोटू राम ने स्वयं इस विसंगति को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था "जो हम एक रुपये प्रति सेर निर्यात करते थे, वह एक छटाक या एक तोला प्रति रुपये में वापस आता था।"

यह कथन उनकी उस पीड़ा को व्यक्त करता है जो वे उपनिवेशवादी व्यापारिक असमानता से अनुभव करते थे। ब्रिटिश शासन की इस नीति के कारण भारतीय उद्योग-धंधे नष्ट हो गए थे और स्थानीय कारीगरों की रोज़ी-रोटी छिन गई थी। पंजाब में कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प जैसे परंपरागत उद्योग तेज़ी से समाप्त होते जा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में छोटू राम ने महसूस किया कि यदि पंजाब को आत्मनिर्भर बनाना है तो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

3. औद्योगीकरण की आवश्यकता पर उनका दृष्टिकोण

सर छोटू राम ने पंजाब की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में औद्योगीकरण को अत्यंत आवश्यक माना। उनका प्रमुख तर्क यह था कि कृषि अकेले प्रांत को पर्याप्त समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि कृषि से स्वतंत्र उद्योगों विशेषकर ग्रामीण आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को व्यापक पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उनके विचारानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और कारीगरों के पास कृषि ऋतु के दौरान काफी अवकाश होता है, जिसका यदि कुटीर उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मिट्टी के बर्तन आदि के माध्यम से उत्पादक उपयोग किया जाए तो उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ बेकारी की समस्या भी कम हो सकती है। उन्होंने बार-बार ज़ोर दिया कि पंजाब का पूर्ण औद्योगीकरण किए बिना प्रांत के लोगों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना संभव नहीं है।

1 मई 1937 को चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "प्रांत की समृद्धि और बेरोज़गारी की समस्या से निपटने की आवश्यकता, दोनों ही बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। औद्योगीकरण ही एकमात्र कारगर समाधान प्रतीत होता है। यदि हम स्वयं अपने कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित कर सकें, तो हम अपने शिक्षित युवाओं में से अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो उन्हें रोज़गार प्रदान कर सकेंगे।"

4. विधानसभा में यूनियनिस्ट पार्टी की औद्योगिक प्राथमिकताएँ

स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा प्रांत की मिश्रित अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से उन्होंने पंजाब विधानसभा में विशेष प्रयास किए। एक महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "विदेशी वस्तुओं की तुलना में भारत में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने के प्रश्न में कोई दो राय नहीं हो सकती।" उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

सर छोटू राम के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने विधानसभा में अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की। इन प्राथमिकताओं में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख थे:

1. प्रांत के कृषि और औद्योगिक जीवन के आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन का कार्य करना ताकि बेरोज़गारी की समस्या से निपटा जा सके।
2. पूँजीपतियों, बड़े ज़मींदारों और धनी लोगों के हितों पर अनुचित अतिक्रमण किए बिना आम जनता के हितों को बढ़ावा देना।
3. विपणन के तरीकों में सुधार करना, जिसमें आपत्तिजनक बाज़ार प्रथाओं और तौर-तरीकों को दूर करना शामिल था।
4. प्रांत के वाणिज्यिक हितों का अध्ययन और प्रचार करना।

यह संतुलित कार्यक्रम औपनिवेशिक पंजाब में सर छोटू राम की किसान-केंद्रित राजनीति को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें ग्रामीण जनता की रक्षा करते हुए स्वदेशी वस्तुओं एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया।

5. औद्योगिक विकास की प्रमुख नीतियाँ एवं पहलें

5.1 तकनीकी एवं औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना

उनके अनुसार पंजाब में उद्योगों की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा पूँजी का अभाव था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यदि निजी उद्यमी उद्योग लगाने की पहल करें तो सरकार उन्हें तकनीकी, विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 1925 में ही उन्होंने औद्योगिक स्कूलों की स्थापना की योजना को आगे बढ़ाया। इन विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना था ताकि वे स्थानीय उद्योगों में कार्य कर सकें। सरकारी शैक्षिक रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि 1921-22 में लुधियाना इंडस्ट्रियल स्कूल में 286 विद्यार्थी नामांकित थे, जिनकी संख्या 1924-25 तक बढ़कर 340 हो गई। इसी अवधि में अमृतसर तकनीकी विद्यालय में भी 300 से अधिक

© 2026 ललित कुमा, राम सिंह गुरना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विद्यार्थी विभिन्न यांत्रिक एवं औद्योगिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 39 जिला गजटियरों के अनुसार लुधियाना और अमृतसर दोनों स्थानों पर बढ़ती छात्र संख्या, नए ट्रेडों की शुरुआत तथा सरकारी अनुदानों में वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि तकनीकी शिक्षा ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी सेवा के नए अवसर खोल रही थी। इन प्रयासों ने न केवल ग्रामीण शिक्षार्थियों को औद्योगिक कौशल प्रदान किया, बल्कि पंजाब में तकनीकी शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, आधुनिक और रोजगार-केंद्रित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5.2 मंडी जलविद्युत परियोजना

बिजली की पर्याप्त और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मंडी जलविद्युत योजना की मंज़ूरी में प्रभावी भूमिका निभाई। यह परियोजना 1934-35 तक लगभग 6.25 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई। इस परियोजना से पंजाब के कारखानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलने लगी, जो औद्योगिक उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बिजली की उपलब्धता ने न केवल बड़े उद्योगों को बल्कि लघु और कुटीर उद्योगों को भी लाभान्वित किया।

5.3 औद्योगिक अनुसंधान कोष की स्थापना

सर छोटू राम ने उद्योग विभाग के बजट प्रावधानों में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 1938 में देश में पहला औद्योगिक अनुसंधान कोष स्थापित किया। यह कोष उद्योग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए समर्पित था। इस पहल ने पंजाब को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित किया जो औद्योगिक अनुसंधान को गंभीरता से लेता था। यह उस युग में एक अत्यंत प्रगतिशील क़दम था जब अधिकांश प्रांत अनुसंधान पर ध्यान नहीं देते थे।

5.4 निजी निवेश को प्रोत्साहन

उन्होंने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों और शुल्क दरों को उदार बनाया तथा सरकारी खरीद में स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के.टी. शाह को पंजाब के औद्योगिक विकास की व्यापक योजना तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रांत का ज़िलेवार एवं उद्योगवार औद्योगिक सर्वेक्षण करवाकर उन्होंने औद्योगीकरण की ठोस आधारशिला रखी। उन्होंने उद्योगपतियों को राज्य-साझेदारी या निजी स्वामित्व वाली परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्हें तकनीकी ज्ञान और कानूनी संरक्षण की गारंटी दी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम में दो उल्लंघनों की अनुमति देकर उद्योग विभाग से ऋण प्राप्त करने और भूखंड अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की गई। शिक्षित बेरोज़गारों को औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराना तथा महिला औद्योगिक शिक्षा को व्यापक स्तर पर फैलाना उनके प्रमुख योगदानों में शामिल था।

6. स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण: व्यावहारिक कदम

6.1 अखिल भारतीय कला एवं उद्योग प्रदर्शनी

27 दिसंबर 1937 में पंजाब प्रांत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाहौर में अखिल भारतीय कला एवं उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय तथा अन्य प्रांतों के स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दी गई, जिससे पंजाब में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। यह प्रदर्शनी न केवल एक व्यापारिक आयोजन थी बल्कि जन-जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी थी।

6.2 सरकारी विभागों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीद

वर्ष 1939 में पंजाब सरकार ने सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता में थोड़ी भिन्नता होने पर भी विदेशी या गैर-स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा प्रांत के अंदर या अन्य भारतीय प्रांतों में निर्मित स्वदेशी सामानों को खरीदने को प्राथमिकता दी जाए। इन नीतियों को व्यावहारिक रूप देने के लिए सरकार ने प्रांतीय भंडार एवं खरीद विभाग की स्थापना की तथा इसे सरकारी विभागों, व्यक्तिगत माँगों और स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री खरीदने का दायित्व सौंपा।

6.3 केंद्र सरकार से विशेष सिफारिशें

विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करने और पंजाब के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1938 में सर छोटू राम ने केंद्र सरकार से विशेष सिफारिश की, जिसमें उद्यमियों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। उनके प्रयासों से पंजाब में उद्योगों की संख्या 1936 में 71 से बढ़कर 1938 में 98 हो गई तथा निवेश 13 लाख रुपये से बढ़कर 24 लाख रुपये वार्षिक हो गया।

7. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा

बढ़ते औद्योगिक विस्तार के साथ सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु आठ घंटे का कार्य-दिवस, पूर्ण वेतन के साथ साप्ताहिक अवकाश, तथा सेवा-समापन के लिए न्यूनतम एक-माह की नोटिस अवधि जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए। कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में मुआवज़े की व्यवस्था भी कानूनन सुनिश्चित की गई। इस अवधि में श्रमिकों की स्थिति सुधारना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। सर छोटू राम की यह दृष्टि समग्र और संतुलित थी वे केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते थे बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि औद्योगिक विकास का लाभ श्रमिक वर्ग को भी मिले। उनका मानना था कि एक न्यायसंगत औद्योगिक नीति वही है जो उद्यमी और श्रमिक दोनों के हितों की रक्षा करे।

8. विशिष्ट उद्योगों का विकास

इसी नीति के परिणामस्वरूप पानीपत में ऊन प्रसंस्करण एवं स्पिनिंग केंद्र, कांगड़ा और कुल्लू में ऊन कताई केंद्र, तथा हिसार में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम शुरू किए गए। लुधियाना के होज़री उद्योग को 1,20,000 रुपये की विशेष सहायता दी गई, जिसने आगे चलकर भारत के लगभग 98 प्रतिशत होज़री उत्पादन का आधार तैयार किया। लुधियाना होज़री उद्योग को दी गई यह सहायता एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुई। आज लुधियाना विश्व स्तर पर होज़री उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और इसकी नींव सर छोटू राम की उस दूरदर्शी आर्थिक नीति में खोजी जा सकती है। कांगड़ा और कुल्लू के ऊन केंद्रों ने स्थानीय पर्वतीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया।

© 2026 ललित कुमा, राम सिंह गुरना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. कृषि संकट और औद्योगीकरण का अंतर्संबंध

1939 में पंजाब विधानसभा में एक अन्य अवसर पर उन्होंने कृषकों की समस्याओं का समाधान बताते हुए कहा, "कृषकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके सर्वोत्तम उपायों में से एक है प्रांत का पूर्णतः औद्योगीकरण करना और मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ तक मेरे अधिकार में और सरकार के अधिकार में है हम प्रांत का तेज़ी से औद्योगीकरण करने का हर संभव प्रयास करेंगे।" कृषि-प्रधान पंजाब में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु सर छोटू राम ने भारत का पहला "किसान राहत कोष" स्थापित किया, जिसमें सरकार ने प्रतिवर्ष 55 लाख रुपये का योगदान दिया। यह क़दम उस असंगत और तदर्थ राहत-प्रणाली का विकल्प था, जिसने लंबे समय तक ग्रामीण समाज को असुरक्षित छोड़ा था। इस प्रकार उन्होंने कृषि और उद्योग को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए दोनों क्षेत्रों में समन्वित विकास की नीति अपनाई।

10. राजस्व सुधार और आर्थिक संतुलन

प्रांत की राजस्व संरचना में असंतुलन को दूर करने के लिए सर छोटू राम ने बिक्री-कर प्रस्तावित किया, जिसमें 5,000 रुपये से कम वार्षिक बिक्री करने वालों को छूट दी गई। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ किसान पहले से ही आर्थिक दबाव में थे, वहीं शहरी व्यापारी वर्ग प्रांत के 11 करोड़ रुपये राजस्व में केवल 24 लाख रुपये का योगदान देता था। पंजाब में यह कर मात्र 4 आने प्रति 100 रुपये रखा गया, जो मद्रास (10 आने) से काफी कम था। हालाँकि इन सुधारों की आलोचना व्यापारी और साहूकारी वर्ग द्वारा की गई, परंतु सर छोटू राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी नीतियाँ किसानों के हितों को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं और किसी भी दबाव के बावजूद वे इन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे।

11. स्वदेशी आदर्श और राष्ट्रवादी दृष्टि

सर छोटू राम की यह पहल समकालीन राष्ट्रवादी स्वदेशी आदर्श से प्रेरित थी। वे राष्ट्रीय आंदोलन के उस व्यापक दर्शन से प्रभावित थे जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण की बात करता था। हालाँकि वे कांग्रेस से अलग एक राजनीतिक मार्ग पर चलते थे, परंतु आर्थिक स्वावलंबन के प्रश्न पर उनकी सोच राष्ट्रवादी चिंतकों के अनुरूप ही थी। 1941 में विधानसभा में सर छोटू राम ने बताया कि जब उन्होंने पदभार संभाला, तब पूरा पंजाब सूखा, अकाल और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त था, जिसके कारण प्रांत पर भारी अनुत्पादक व्यय पड़ रहा था। उन्होंने अकाल नियंत्रण के लिए तीन वर्षों की अल्प अवधि में ही लाखों रुपये खर्च किए। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने औद्योगिक विकास को गति देना जारी रखा यह उनकी अदम्य इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

12. निष्कर्ष

सर छोटू राम ने पंजाब के औद्योगिक विकास में जो योगदान दिया, वह बहुआयामी और दूरगामी था। उन्होंने एक ऐसे समय में औद्योगीकरण की नींव रखी जब प्रांत सूखे, अकाल और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण से जूझ रहा था। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार थे: तकनीकी विद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना, मंडी जलविद्युत परियोजना जिसने सस्ती बिजली सुनिश्चित की, देश का पहला औद्योगिक अनुसंधान कोष, लुधियाना होज़री जैसे स्थानीय उद्योगों को विशेष सहायता, स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को सरकारी नीति बनाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, और किसान राहत कोष के माध्यम से कृषि-औद्योगिक संतुलन। सर छोटू राम केवल एक किसान-नेता नहीं थे वे एक समग्र आर्थिक सुधारक थे जिन्होंने कृषि, उद्योग, श्रम और राजस्व को एक एकीकृत दृष्टि से देखा। उनकी यह विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा विकास वही है जो ग्रामीण और शहरी, किसान और उद्यमी, श्रमिक और पूँजीपति सभी को साथ लेकर चले।

संदर्भ सूची

1. सर छोटू राम के भाषणों और नीति दस्तावेजों का संग्रह: औद्योगिक क्षेत्र में योगदान, पंजाब सरकार अभिलेखागार, लाहौर, 1925–1941
2. पंजाब विधान सभा बहसें, पंजाब सरकार प्रकाशन, लाहौर, 1936–1941
3. लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वार्षिक सामान्य सभा की कार्यवाही रिपोर्ट. 1 मई 1937, लाहौर
4. पंजाब सरकार, उद्योग विभाग, औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्टें – जिलावार और उद्योगवार, लाहौर, 1936–1939
5. के. टी. शाह आयोग, पंजाब के औद्योगिक विकास की व्यापक योजना, लाहौर, 1937
6. पंजाब लोक निर्माण विभाग, मंडी जलविद्युत परियोजना अभिलेख, लाहौर, 1934–1935.
7. हरि राम गुप्ता, सर छोटू राम: जीवन और कार्य , मिनर्वा बुक शॉप, लाहौर, 1944.
8. इमरान अली, साम्राज्यवाद के अधीन पंजाब, 1885–1947, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन,1988
9. पंजाब राजस्व विभाग, किसान राहत कोष की वार्षिक रिपोर्ट, लाहौर, 1938–1941.
10. पंजाब प्रांतीय स्टोर्स एंड परचेज विभाग, सरकारी परिपत्र – स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के निर्देश, लाहौर,1939
11. अखिल भारतीय कला और उद्योग प्रदर्शनी समिति, प्रदर्शनी रिपोर्ट और कार्यवाही, लाहौर, 27 दिसंबर 1937
12. पंजाब श्रम विभाग। औद्योगिक श्रमिकों के अधिकार और कार्य स्थितियाँ. लाहौर, 1938–1940।
13. ताई योंग तान, गैरीसन राज्य: औपनिवेशिक पंजाब में सैन्य, सरकार और समाज, 1849–1947. नई दिल्ली, 2005.
14. लुधियाना होजरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, होजरी उद्योग का ऐतिहासिक विकास – शताब्दी स्मारिका. लुधियाना, 2000.
15. बी.आर. नंदा, भारतीय राजनीति में यूनियनिस्ट पार्टी और पंजाब. नेशनल आर्काइव्स पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1978.
16. पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम संशोधन दस्तावेज: उद्योग विभाग ऋण और प्लॉट अधिग्रहण प्रावधान. उद्योग विभाग, लाहौर, 1936.
17. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, गृह विभाग फाइलें, पंजाब औद्योगिक नीति और स्वदेशी आंदोलन, नई दिल्ली, 1930–1940

© 2026 ललित कुमा, राम सिंह गुरना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

18. मजूमदार, रमेश चंद्र, और अन्य, भारत का उन्नत इतिहास, बी.सी. लॉ मेमोरियल ट्रस्ट, कलकत्ता, 1961.
19. पंजाब औद्योगिक अनुसंधान कोष, स्थापना दस्तावेज और प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, उद्योग विभाग, लाहौर, 1937

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

ललित कुमार देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब) में इतिहास विषय के पीएच.डी. शोधार्थी हैं। आपका शोध विषय "चौधरी सर छोटू राम एवं कृषक वर्ग का एक ऐतिहासिक अध्ययन" है। इतिहास के क्षेत्र में आपका शोध एवं लेखन कार्य निरंतर जारी है। आपके दो शोध-पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं तथा आपने लगभग चार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सेमिनारों में अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए हैं।
आप बी.ए. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) की इतिहास विषयक पुस्तक "आइडिया ऑफ भारत" के लेखक हैं। इसके अतिरिक्त आपके शोधपरक लेख दो संपादित पुस्तकों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इतिहास, कृषक आंदोलनों, ग्रामीण समाज तथा पंजाब के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास के अध्ययन एवं अनुसंधान में आपकी विशेष रुचि है। युवा शोधकर्ता के रूप में आप ऐतिहासिक तथ्यों के गहन विश्लेषण तथा कृषक वर्ग से संबंधित विषयों पर निरंतर शोधरत हैं।

डॉ. राम सिंह गुरना एक प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद् हैं। आपने पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से इतिहास विषय में एम.ए. (1985) एवं एम.फिल. (1986) तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पीएच.डी. (2006) की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1990 से 2021 तक आपने ए.एस. कॉलेज, खन्ना (पंजाब) में अध्यापन कार्य किया। वर्तमान में आप देश भगत विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। लगभग 32 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव के दौरान आपके निर्देशन में 15 से अधिक एम.फिल. एवं 10 से अधिक पीएच.डी. शोधार्थी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आपकी 6 पुस्तकें तथा 22 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

© 2026 ललित कुमा, राम सिंह गुरना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/